an atrocity on him by the Vice-Chairman. What kind of atrocity can t<here be between two males.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PINESH GOSWAMI): We take it in the spirit in which he has said it. Now, Mr. Mathur to start the discussion.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, if the hon. Member feels that way, I can withdraw it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We take it in the spirit in which he has said it. Now, Mr. Mathur, you can start the discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER GIVEN IN RAJYA SABHA ON 25TH JULY, 1980, TO STARRED QUESTION 41 REGARDING NHAVA SHEVA PORT IN BOMBAY

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : समझौता हो गया 10-मिनट। श्रीमन्, नोवा शेवा पोर्ट का विषय किसी एक दल का या प्रांत का नहीं है, यह बहुत राष्ट्रीय महत्व का विषय है। प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तीन चार दिन पहले यहां के मंत्री से मिल कर गये। यदि यह केवल महाराष्ट्र का विषय होता तो शायद हमें चिंता नहीं होती। सारा महाराष्ट्र भारत का है और संपूर्ण भारत महाराष्ट्र का है। इस दृष्टिकोण से नोवा शेवा पोर्ट को हमें देखना चाहिये।

श्रीमन्, मैं तकनीकी बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की बंदिश है। यह विषय आज से नहीं 20 साल से ऊपर से चला आ रहा है। सर्वप्रथम 1961 में यूनाइटेड नेशन्स के विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि बम्बई पोर्ट को एक्सपेण्ड किया जाये तथा नोवा शेवा पोर्ट जैसी योजना को हाथ में लिया जाये। उसके पश्चात् कितने ही वर्किंग ग्रुप आदि बने। मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, तकनीकी विषय पर नहीं जाऊंगा। अंतिम रिपोर्ट जो हमारे सामने है पांडे कमेटी की रिपोर्ट मैं केवल उसकी ओर श्रीमन्, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उसमें जो सुझाव आदि हैं समय के अभाव के कारण उनका उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन पांडे कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्धित भाग पढ़ना चाहता हूं :

"While the foregoing considerations should suffice to justify the case for construction of an ancillary port at Nhava Sheva, two more points deserve attention. In our view, there is an urgent need for development of a deep draft port in the country which can receive modern ships, particularly those carrying container and bulk cargo. We understand from technical experts that Nhava Sheva is the only site available in the country that has a natural draft of 14 to 15 metres. No other port site either on the western or on the eastern coast of India can match the draft provided at Nhava Sheva. Secondly— this is an equally significant consideration—the proposed port at Nhava Sheva is located within the vicinity of Bombay port system which is the major port of call for liner ships. This particular site will have the advantage of not only serving tramp trade but also liner trade of the Country."

There is another portion which says:

"The long-term solution to Bombay Port's congestion will be by significant additions to its capacity. Such capacity expansion is not feasible in the existing port. There is an urgent need for the development of a deep draft port in the country which can receive modern ships, particularly those carrying container and bulk cargo. Nhava Sheva is the only site technically suitable for the development of a deep draft port."

माननीय मंत्री महोदय का लोक सभा में उत्तर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नोवा शेवा पोर्ट की योजना को हमने

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

समाप्त नहीं किया है। दूसरे, उन्होंने कहा–कुछ आबजेक्शंन थे। वह आबजेक्शंस क्या थे? मैं उनका उत्तर पढ़ देता हूं :

"There were same objections by the environmentalists against installation of ONGC for their supply base and fabrication of Drilling platform of Mazagon Dock, on Nhava Island."

He also said:

"Public Investment Board has cleared the proposal for preparation of Detailed Project Report. Further action is under consideration."

तो गवर्नमेंट के कहने के अनुसार सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है केवल उस को कार्यान्वित करना शेष है। लेकिन मुख्य चीज जो मेरे सामने है वह यह कि कठिनाई कहां है? मंत्री जी निश्चित रूप से–मैं जानता हूं उन की अदाओं को–मना करेंगे, लेकिन 7 जून, 1980 को आप के मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बम्बई पोर्ट के लोगों को और दूसरे सम्बन्धित लोगों को पत्र लिखा है जिस की सम्बन्धित पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं :—

"We have not yet been able to issue the sanction of Detailed Project Report as we have been advised by Prime Minister's Office not to take any further action till the issues raised by 'Save' Bombay Committee, have been considered and decided upon. As regards social cost benefit study, we have advised Bombay Port Trust to undertake it."

श्रीमन, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि काम रोकने की यह जो गलती हुई है वह क्यों हुई है? आखिर जिस को "सेव बम्बई कमेटी" कहा जाता है वे कौन लोग हैं। मिस्टर करंजिया हैं, करंजिया साहब को सब जानते हैं, बिल्ट्ज के एडीटर हैं और प्रधान मंत्री महोदया के परिवार से बराबर सम्बन्धित रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं। क्या इतने महत्वपूर्ण विषय को केवल इसलिये बट्टेखाते डाला जायेगा कि कुछ ऐसे एलीट, जिन को हिन्दी में सफेदपोश कहते है, इस पर आपत्ति कर रहे हैं। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि अगर उन्होंने एतराज किये हैं तो वे क्या हैं। मेरी जानकारी में उन की आपत्ति वहां पर जो ओ० एन० जी० सी० का बेस बनने वाली है उस के बारे में है। दूसरा एतराज उन्होंने लिया है मझगांव डाक के बारे में मझगांव डाक वहां अपनी ड्रिलिंग बेस बना चाहता है। सब जानते है कि मझगांव डाक क्या है। अगर हमारी सुरक्षा के लिये जहाज बनाने के काम के लिये नोवा सेवा पोर्ट के अलावा दूसरा स्थान नहीं है तो क्या कुछ सफेदपोश लोगों को, जो अच्छे रईस लोग हैं, उन्हे गन्ध न आये, बू न आ उनके कपड़े खराब न हों इसलिये क्या हम देश की सुरक्षा प्रश्न को छोड़ देंगें, क्या हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन को भला देंगे? मंत्री महोदय से मेरा सीधा सवाल है कि जब आप ने यह मान लिय है कि आप कार्यवाही करने वाले हैं तब धान मंत्री के सेक्रेटेरिएट की ओर से यह रुकावट क्यों डाली गयी? अगर कावट डाली गयी है तो वह कब समाप्त की जायेगी? दूसरे इस बात की कितनी जल्दी सफाई करेंगे? कारण जैसा कहा है कन्टेनर्स का है। मैं एक विषय और लेता हूं। उदाहरणार्थ रूस की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो आप के गरम कपड़े हैं ऊनी कपड़े हैं इन को कन्टेनर्स में भेजिये। अब कन्टेनर्स क्या हैं, कैसे हैं, इस में मैं नहीं जाना चाहता। मेरे ध्यान में सिर्फ एक तूतीकोरिन पोर्ट है जहां इस प्रकार की व्यवस्था है। लोगों ने कभी यह उसके बारे

में भी कहा था कुछ एक्सपर्टस ने, आप के सलाहकारों ने कहा था कि यह लाभदायक नहीं होगा। इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन नार्मली 10 परसेंट रिटर्न चाहता है? दूसरी एक्सपर्ट ओपोनियन यह है कि यह 14.7 परसेंट रिटर्न देगा। मुझे मालूम है कि तूतीकोरिन पोर्ट जब बढ़ाया गया था और उस को मेजर पोर्ट स्वीकार किया गया तो सब ने यह सन्देह प्रकट किया था कि तूतीकोरिन रिटर्न नहीं होगा। मैं वहां इसी मास के प्रारम्भ में कमेटी में वहां गया था, हम लोग देख कर आये हैं। उन्होंने कन्टेनर सर्विस शुरू की है और उन्होंने बहुत अच्छा व्यापार को बढ़ाया है। इसी तरह व्यापार हमारे नोवा शेवा पोर्ट से बढ़ेगा। कुछ नहीं तो जितने दिन कन्जेशन होता है (*Interruptions*). या ड्रजिंग के लिये समय चला जाता है तो लगभग 1500 रुपये पर शिपिंग दिन हमारा जाता है। कितने करोड़ रुपये की हानि है। मेरा निवेदन मंत्री महोदय से है कि इन प्रश्नों का जवाब दे दें। दूसरे शीघ्र से शीघ्र एक नोवा शेवा डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाय जिससे उस के काम में बाधा न पड़े और जिस से 20 साल से लटकती आई योजना को आप अगले पांच साल में पूरा कर के देश का भला कर सकें। घन्टी बज रही है, आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो घन्टे-पौन घन्टे और बात कही जा सकती है।

नौवहन तथा परिवहन और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : उपसभाध्यक्ष जी, जो भी अभी माननीय सदस्य श्री माथुर ने अपने विचार व्यक्त किये, इस के संबंध में मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है और मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं सिवाय दो एक बातों के उस में कहीं अंतर नहीं होगा। प्रश्न यह है कि माथुर साहब नोवा शेवा में पोर्ट की स्थापना चाहते हैं या इस अवसर को इस बात के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वह यह बतलायें कि उस पोर्ट की स्थापना होनी चाहिये। इस के अलावा जैसा कि उन्होंने कहा अभी नाम लिया बंबई सेव कमेटी के संबंध में और एक व्यक्ति का भी नाम लिया और बताया कि उन का कुछ व्यक्तिगत संबंध है, किसी से पारिवारिक संबंध हैं और इसलिये यहां इस तरह की बातें उठायी जा रही हैं और इस मौके को वह उस के लिये इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक नोवा शेवा प्रोजेक्ट का सवाल है, मैंने उस सदन में भी बतलाया, और उन्होंने हमारे मंत्रालय के किसी पत्र का भी जिक्र किया, उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोई जानकारी इस के संबंध में नहीं है। हमारे दूसरे सदन के एक मित्र ने अभी एक चिट्ठी लिखी इसी संबंध में, तो मैं समझ सकता हूं कि आप दोनों आदमियों का तालमेल इस संबंध में जरूर होगा और इसीलिये उन्होंने चिट्ठी लिखी और आप ने इस सवाल को उठाया।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लेकिन आप फाइल नहीं देखेंगे?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : देख लूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र जिस बात का जिक्र करना चाहते हैं, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब हम नोवा शेवा पर अभी डी० पी० आर० कमीशन करने वाले थे, पहले तो जो स्टेजेज हैं उन को मैं बतला देना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन का एक वर्किंग ग्रुप इस के लिये कांस्टीट्यूट हुआ था। उस वर्किंग ग्रुप ने यह बतलाया कि नोवा शेवा में यह पोर्ट स्थापित किया

[श्री अनन्त प्रसाद शर्मा]

जाय । इस के औचित्य की बात उन्होंने बतलायी है। उस के बाद जो पब्लिक इंवे-स्टमेंट ....

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): When was it approved by the Planning Commission?

SHRI A. P. SHARMA; You want the date?

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): November 1979.

SHRI A. P. SHARMA: "The Working Group of the Planning Commission concluded that having regard to the existing condition at Bombay Port and the projections of traffic requirements for the coming years, we consider that the proposal for Nhava **Sheva Port** Project is justified on techno-economic consideration."

उस की डेट जानना चाहते हैं, वह है अप्रैल, 1980 तो मैं उपसभापति जी, यह कह रहा था कि प्लानिंग कमीशन के स्टेडी ग्रुप ने इस के औचित्य को बतलाया और उस के बाद शायद आगे प्रश्न करने की आवश्यकता न हो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि डी०पी०आर० Detailed Project Report— के बारे में मैंने बतलाया कि उस को हम कमीशन करने वाले थे तब तक हमारे बंबई के जो इंवायरेनमेंटलिस्ट मित्र हैं जिस में माथुर साहब के मित्र भी होंगे—क्योंकि कहा जाता है कि कुछ खास लोगों की तरफ से यह सेव बंबई कमेटी बनी हुई है, तो उन खास लोगों में आप के कुछ खास लोग जरूर होंगें, इस में मुझे कोई संदेह नहीं है, तो वह जो इंवायरेनमेंटलिस्ट्स हैं उन लोगों की तरफ से यह बातें बतलायी गयी और उन्होंने बतलाया क्या, कुछ आपत्तियां उन्होंने उठायीं हैं। और मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि क्या आपत्ति उन्होंने उठायी है। उन को आपत्ति थी :

"Installation of **ONGC** for **their** supply base and fabrication of drilling platform on the Mazagon Dock off Nhava Island."

यह उनकी आपत्ति थी और जब यह आपत्ति उठी तो हमारे साथी हमारे मित्र मिनिस्टर आफ स्टेट फार डिफेंस प्रोडक्शन इस बात की छानबीन करने के लिये गये। इन्होंने इन लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद रिपोर्ट भी सबमिट की। अब कही जाती है रूकावट की बात तो मैं इसके संबंध में खुलासा कर देना चाहता हूं। अगर आप इस चीज को सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। एक्शन स्टे कर दिया गया है। क्यों एक्शन स्ट कर दिया गया है यह आपत्ति लोगों की तरफ से बीच में आई। अब इसकी छानबीन कर रहे हैं। किसने कहा है कि अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ रहे हैं यह उल्लेख किया गया है :

"The Ministry of Shipping and Transport should examine this further in the light of the suggestions of the Minister"—here Minister means the Minister of State for Defence Production—"before sanctioning the detailed project."

"Don't sanction this detailed project report."

इसमें न कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। सेंक्शन करने की बात है तो इसमें यह नहीं कहा गया

यह आपत्ति जो बीच में आकर खड़ी हुई है अगर इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, इसके संबंध में अगर रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के ऊपर गौर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है तो इस में क्या दिक्कत हमारे सामने आती है। जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि इसी सदन में इस विषय पर एक प्रश्न था। हमारे बहुत

पुराने मित्र श्री कुलकर्णी जो हमारे साथ बैठते थ अब उधर बैठे हुए हैं . . . (*Interruptions*).

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र): आप जीत कर उधर चले गये हैं हम लोग इधर ही रह गये हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आपकी अगर कहानी कहूंगा तो मुश्किल हो जायेगी। आप उधर हम को बुलाना चाहते हैं तो इधर कौन बैठेगा (*Interruptions*). आप लोगों की मेहरबानी से हम इधर बैठे हुए हैं। अगर आपकी मेहरबानी नहीं होती...

(*Interruptions*).

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : हम लोग उधर आ सकते हैं। इधर रहे या उधर रहें हम को कदम मिलाकर चलना है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : हमारे पुराने मित्र श्री कुलकर्णी हमारे साथ बैठते थे और उन्होंने कहा कि हम उधर बैठ भी सकते हैं। मैं इसकी आशा करता हूं कि वह जल्दी जल्दी इसका फैसला करें और हम लोगों के साथ बैठें। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं यह कह रहा था आज से कुछ दिन पहले जो प्रश्न आया इसी विषय पर आया था। मेरे पुराने दोस्त होते हुए भी यह नहीं समझते और उन्होंने यह आवाज कसी कि बुलाओ उनको ताकि वह हमारा चैलेंज फेस करें। इसमें चैलेंज क्या है। जहां तक चैलेंज का सवाल है वहां हम इसे फेस करने से घबराते नहीं है लेकिन इसमें चैलेज कोई है नहीं। यह हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है इसलिये मैं खासतौर से साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने दूसरे सदन में प्रश्नोत्तर में कहा कि इन बातों पर विचार किया जा रहा है। जो मिनिस्टर आफ स्टेट फार डिफेंस प्रोडेक्शन की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर विचार करने के बाद ही इसके बारे में हम फैसला करेंगे। फैसला करने का मतलब यह नहीं है कि हम फैसला नोवा शेवा पोर्ट को एस्टाब्लिस करने का करेंगे। जो आब्जेक्शन रेज किये गये हैं उन पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप मान तो गये हैं। आपने यह मान लिया है कि जो आब्जेक्शन आये हैं उन पर विचार करेंगे . . .

(*Interruptions*).

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : माथुर साहब, मैं आपको एक इन्फरमेशन देना चाहता हूं कि इसके बाद भी पी० आई० बी० यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से क्लीयरेंस की जरूरत पड़ेगी। जब डी० पी० आर० डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आयेगी तो उसके इन्वेस्टीगेशन के लिये हमको पी० आई० बी० के पास भेजना पड़ेगा। वहां उसकी क्लीयरेंस के ऊपर विचार होगा। आपकी तसल्ली के लिये मैं आपको बता दूं कि जो ड्राफ्ट फाइव इयर प्लान 1980-1985 का है उसमें 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। (*Interruptions*) श्रीमन्, मैं यह कहा रहा था कि इसके लिए 80 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जा रहा है . . . (*Interruptions*). मैं नोवा शेवा पोर्ट की बात कह रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Bagaitkar has yet to ask his questions; Mr. Kulkarni has yet t0 ask his questions.

SHRI A. P. SHARMA: After I speak, I hope Mr. Kulkarni may not have any question to ask. I am just now concluding.

श्रीमन्, मैंने यह कहा है कि इसके लिये ड्राफ्ट फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में 80 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया

[Shri A. P. Sharma]

गया है और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस पर टोटल कास्ट का जो अन्दाजा लगाया गया है वह 175 करोड़ रुपयों का है। इस पोर्ट को इस्टेब्लिस करने में 175 करोड़ रुपये लगेंगे, ऐसा अन्दाजा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Dr. Zakaiia. Mr. Kulkarni, are you asking your questions or are you satisfied?

SHRI S. W. DHABE: Sir, Dr. Zakaria is afraid because he challenged the Minister.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, Mr. A. P. Sharma is a good friend of mine and I respect him for the friendship which he has maintained, though we are on opposite sides. The problems are only two. I do not want to go into the questions already touched. He has fairly replied those questions. There **are** only two problems here, on which, Mr. sharma, you will have either to eat your words or concede my demand. Only two problems I am mentioning, and I am quoting for your information. Mr. Sharma, you have to look through the proceedings of the House. When you were absent from here, your colleague lion. Shri Buta Singh had conceded in the House that the PIB has cleared this project. He has already conceded that. So either you are wrong or telling something which is not correct or Shri Buta Singh, being a little bit young chap, might have slipped somewhere: might not have seen the file correctly. That is No. 1.

Now I am posing my real question, on which the Minister has to say something. He does not believe in pollution. He has already made it very clear that *Ganga Mata ka bhakt hai.* Once for all he is saying that it is the purest river. Now here is something which I may quote for his information. To the name taken, the > Prime Minister's secretariat has issued a stay order. I quote from the 'Hindustan Times' the Non-Official Gazette of the Government of India. What did they say on July 29? quote;

"Prime Minister Indira Gandhi has said that until a huge segment of humanity in the developing world was condemned to poverty, any discussion on the "protection of our environment or of preserving the ecological balance or of saving wildlife' could not have any meaning."

This is the message given by our hon. Prime Minister to the "first global conference on the future". Having seen this, I was enthused. Now the stay order has been removed. There are not two faces of the Prime Minister, though some people have written a book on that; I d0 not believe in that. The Prime Minister is very sincere in saying that it is not for the people in the developing world. You, Mr. Sharma, are pure and have issued a stay order. This v/ay we have lost Rs. 327 crores during the last ten years. I am coming to the second question and I am finishing. Here is a telex message from the hon. Chief Minister of Maharashtra;

"Chief Minister held discussions with Dr. Salim Ali on 25th instant."

Dr. Salim Ali is one of the environmentalists, sir, he is really a nature-lover. He is a very respected and a knowledgeable person. Unfortunately he is held by all the cinema actors and rich people. She is not here. She is not concerned because she may not act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Cinema actors", you said.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Wh0 is not here?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You do not provoke rne here for Heaven's sake. Otherwise, *jhagda* will start here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); You said, "cinema actors" only.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mr. Minister, whose problem is this? It is of those rich people who are very few, not even hundreds between Puran and outer Bombay, near Bombay. All the poverty-stricken people live at Mal-bari. The telex message says:

> Dr. Salim Ali on 29th instant when some of the active leading environmentalists were present concerning Nhava Sheva Port, it transpired during the discussions that the environmentalists had no objection to the Nhava Sheva Port but only wanted the development of the hinterland..."

This is their latest discussion. Further, Sir, the Maharashtra Government desires:

"It would be eminently desirable to have the stay on the commissioning of the project report of the port by the Ministry of Transport and Shipping vacated."

Though it was reported that the Prime Minister had issued the stay order it seems, unfortunately, Mr. Sharma has to carry that baby because he is handling this matter. These are two questions. Mr. Minister, I want to know this. We know, Dr. Salim Ali, the environmentalist, had no objection. Why do you not rise to the occasion and assure here and now that the Nhava Sheva Port's stay order will be vacated? The preparation of the DPR does not mean putting money tomorrow morning. I do not want to blame your colleague, the Minister who visited Bombay. The problem is that of vacating the stay order. DPR is not being done within 24 hours. It will take another six months. Till then no investment can be made. The PIB has cleared the investment. Either you are fooling this House or your friend did not understand the problem at all. You say that the Prime Minister is totally wrong because in India she has taken one position and in the world body she has taken another position which seem contradictory.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Jha.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं। आप भी नोट कर लें।

THE VICE-CHAIRMAN **(SHRI** DINESH GOSWAMI): Mr. Minister, you will reply to all the questions. Mr. Narsingh Narain Pandey, I will call you; your name is there.

SHRI A. P. SHARMA: Should I not reply to him?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): No. Excuse me. The procedure is that the fir3t Member asks questions and the Minister replies. Then all the other Members will ask questions and the Minister replies to all of them at the end.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, पहला मेरा सवाल है कि मंत्री महोदय ने कहा कि 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, विजुलाइज किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि नोवा शेवा में पोर्ट बनाने की योजना कितने साल पहले की है। जहां तक मुझे मालूम है 15 साल से यह बात चल रही है। उस वक्त इस पर कितना अमाउन्ट खर्च होता और अब कितने की सम्भावना है, अब कितना लगेगा, जो दाम बढ़ गये हैं उसके संदर्भ में ?

दूसरा सवाल है कि नोवा शेवा पोर्ट बनाने से क्या यह बात सही नहीं है कि

[श्री शिव चन्द्र झा]

उस इलाके का विकास होगा, रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा? क्या इससे यह बात होगी या नहीं होगी? पोल्यूशन की जो बात है, पोल्यूशन होगा, वातावरण बिगड़ेगा, इसमे वेस्टेड इंटरेस्ट निहित स्वार्थ के लोगों का हाथ है। इसको बिगाड़ने के लिये और अपने मतलब को साधने के लिये इस तरह की बात कही जा रही है।

चौथा और आखिरी सवाल पैसों का है। क्या यह बात सही है कि पोर्ट ट्रस्ट का जो पैसा है और जो उसका इंटरेस्ट आता है उससे आपका यह पोर्ट बन जायेगा। आपको इसके लिये कोई नया प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात पर गौर करें कि पोर्ट ट्रस्ट का जो पैसा है उसके इंटरेस्ट से ही यह बन जायेगा आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। अब मेरा अन्तिम सवाल यह है कि यह सब गड़बड़ जो है कि डिफेंस ने यह कहा, उसने वह कहा, इसने यह कहा इसके लिये क्या आप संसद सदस्यों की एक छोटी सी कमेटी बना कर इसकी जांच करायेंगे? यह मेरे पांच सवाल है।

श्री सदाशिव बागाईतकर: उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बातें कही गई है, कुलकर्णी साहब ने टेलेक्स का उल्लेख किया है उनको मैं छोड़ देना चाहता हूं। असल में सवाल यह है कि एक तरफ तो यह नियोजन की डींग हांक रहे हैं लेकिन 1960 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 20 साल हुए। माननीय मंत्री जी जरा सुनिये। 1960 में प्रोजेक्ट के लिये 51 करोड़ रुपये आंके गये और 1975 में 98.89 करोड़ आंका गया था। अब करंट एस्टीमेट जो बोम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने किया है वह 109.90 लाख का किया है यानी 20 साल एक प्रोजेक्ट का फैसला आप नहीं कर पाये। इसका नतीजा यह हुआ है 1960 में जहां पर 51 करोड़ खर्च होना था वह 109 करोड़ हो गया। साथ ही साथ और भी यह हुआ कि 1961-62 से लेकर 1977-78 तक 15000 शिप बेस का लास हुआ है। 87 करोड़ का लास आपने किया है। कौन इसके लिये जिम्मेदार है। और फिर भी आप इसमे ओ० एन० जी० सी० का इकोलोजी का बता कर टाले जा रहे हैं। इसमें बात यह है कि टेक्निकल रिपोर्ट्स में कोई मतभेद नहीं है। सरकार में शिपिंग एंड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री ने वेस्टर्न पोर्ट्स का जो सर्वे किया है कि आपके नोवा शेवा पोर्ट में 15 से 18 मीटर ड्राफ्ट है, इसके अलावा और किसी जगह नहीं है जिससे डीप सी पोर्ट बन सके। यह आपकी टेक्निकल रिपोर्ट है। यू० एन० ओ० के भी एक्सपर्ट्स आये थे जिन्होंने यह सारा सर्वे कर के रिकमेंड कर दिया है। उसके बाद इतना सारा कुछ हो जाने के बाद भी आप इसका फैसला नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी भी कुछ है या नहीं। 1961 में जो खर्च था और जो अब लगेगा वह अब 87 करोड़ का लास हुआ है और इकोनोमी पर बुरा असर हो रहा है। इसके लिये कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी पर नहीं है, यह मुझे लग रहा है।

अब इकोलोजी की बात आती है। जो उनको ओब्जेक्शन इस पर था उसमें उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि ओ० एन० जी० सी० को जो सहूलियत मे उससे इकोलोजी का बैलेंस बिगड़ जायेगा। लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मामला इकोलोजी का नहीं है यह केवल ढकोसला है। डा० सलीम जैसे कुछ अच्छे लोग बेचारे उस में फंस गये हैं। असल में मामला यह है कि उस

इलाके में जो बड़े रईस लोग हैं, लैंड लार्ड्स हैं, जिनकी जमीन वहां फंसी है, उन्हें यह झमेला लगता है कि लैंड हमारी एक्वायर हो जायेगी, इन लोगों को नुक्सान है इसलिये उन्होंने यह ढकोसला खड़ा कर दिया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दूसरा पक्ष यह है कि फिशिंग पोर्ट बनाने की बात वहां पर है। इससे उनको बदबू आयेगी जिससे उनको बेचैनी महसूस होगी। ऐसे रईस लोग वहां रहते हैं। वह इलाका आपने देखा होगा। इसलिये उन्होंने इकोलोजी का ढकोसला बनाया है। अब मुझे यह जानना है कि इकोलोजी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के समूह ने प्राइम-मिनिस्टर के पास सिर्फ एक तजवीज भेजी तो उस पर 20 साल तक आपने उसका टेक्निकल अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जो देश की जरूरत है एक डीप-सी पोर्ट की वह सारी यहां हो सकती है। उसकी कोई दूसरी जगह हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप जो विलम्ब कर रहे हैं, इस विलम्ब से नुक्सान हुआ है, विकास पर बुरा असर हुआ है, कास्ट स्ट्रक्चर पर बुरा असर हुआ है। आठ-आठ महीने वहां पर मेन स्ट्रीम में फारेन के शिप्स रहे हैं क्योंकि वहां उनको बर्थ नहीं मिलता है। यह जो इतना विलम्ब हुआ है उससे बहुत नुकसान हुआ है। बाम्बे पोर्ट दुनिया का सब से अच्छा पोर्ट माना जाता है। 90% अकुपेंसी बाम्बे पोर्ट की रही है जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार 67% से ज्यादा अकुपेंसी किसी पोर्ट की नहीं होनी चाहिये। यह माना जाता है कि बाम्बे की पोर्ट की 90% अकुपेंसी होने की वजह से नतीजा यह हो रहा है कि शिप्स के लिए रिपेयर्स और ड्रेजिंग का काम जो किसी भी डीप सी पोर्ट में होना है वह हो नहीं पा रहा है। इसलिये बम्बई में शिपिंग इतनी बढ़ गयी है कि कुछ दिनों के बाद बम्बई कलकत्ता की जो स्थिति है उसमें वह होने की गुंजाइश है, खतरा है। तो यह भी नुकसान आपकी नीति के चलते, निर्णय न करने की जो नीति है या गलत निर्णय करने की नीति है उसके चलते होगा। यह सारा नुकसान हुआ है। मैं आपसे यह चाहूंगा कि, कुलकर्णी साहब ने जो टेलेक्स पढ़ा है, वह टेलेक्स मेरे पास भी आया है, तो यह देखते हुए कि इकोलाजी वालों का उसमें कोई आब्जेक्शन नहीं रहा है, वे उसके लिये तैयार हो गये हैं फिर क्या सरकार इसकी तुरन्त घोषणा नहीं करेगी कि :

Nhava-Sheva project has been finally cleared and accepted by the Government.

उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट अथारिटी आप कब तैयार करेंगे, क्या करेंगे। फिर उसके लिए एक महीने का समय लगे, दो महीने का लगे, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा समय लगे, लेकिन इन प्रिंसीपुल आप अगर ऐलान नहीं करेंगे कि,

Nhava-Sheva project has been finally approved and accepted by the Government.

यह बात अगर आप नहीं करेंगे तो वाद-विवाद कुछ ऐसा चलेगा, 20 साल तक तो मामला चला है तो वर्षों तक और चलता रहेगा। देश का सारा नुकसान होगा जिसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसकी सफाई दें।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Uttar Pradesh): This is a very interesting case of negligence on the part of the Shipping and Transport Ministry. The Minister has given two replies. I will quote what he said on the 25th July, 1980. He said:

"The Nhava-Sheva Project is not being held up on account of nonavailability of funds. Environmentalists had raised, however, some objections against the Sassoon Fish-

[Shri Narsingh Narain Pande]

ing Harbour in Bombay and ONGOs supply base at Nhava Island. The proposal is under consideration of the Government."

There are two objections, one about the fishing harbour and the other about the ONGC base. This is one aspect of the matter. It is on the basis of this reply that we are discussing today.

But on the 31st July 1980 the Minister replied to another question on this subject in the Lok Sabha. He said:

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There were some objections by the environmentalists against installation of ONGC for their supply base and fabrication of drilling platform of Mazagon Dock, on Nhava Island.

(d) Public Investment Board has cleared the proposal for preparation of detailed project report. Further action is under consideration.

These are the two replies before yoti. These two replies have created some misconception in the minds of th« Members of this House. What is now the real position? Hag the Public Investment Board given its clearance or not? If you go to the background history of this, there was another reply in the Lok Sabha on the 2nd August, 1978, given to S.Q. No. 260 tabled by Shri D. B. Patil. Shri Chand Ram was then the Shipping Minister. He said:

"In 1960, Government of India through the United Nations Technical Assistance Operations, invited an expert to visit India and advise, among other matters, on the modernisation of Bombay Docks. One flf his recommendations related to Kie preparation of a Master Plan for the efficient future development of Bombay Port. The Master Plan for the port prepared by their consultants in 1970 recommended construction of an ancillary port at Nhava-Sheva. A high-level working group has recently been constituted by Planning Commission to study the proposed Nhava-Sheva scheme from all angles."

Sir, as the Minister has already said, a group of the Planning Commission has already recommended this and he has already quoted this. But, Sir, in the year 1979, on the 23rd March, in reply to Starred Question 522 in the Lok Sabha something else has been said about this project. But what Mr. Mathur has said is that this is due to the Government of Shrimati Indira Gandhi and that is why it has been delayed? I can point out that it is your Minister only who has denied this and if I go into details, it will he ma-le known that it is nobody else but your Minister and your Government who are responsible for the delay in this project. I do not want to mention all that. But if you want, I may read out some of the portions.

SHRI JAGDISH PRASAD MA THUR: My dear friend, in 1978 _______

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DTNESH GOSWAMI): Let us not go into that controversy now.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: But in the year 1978 ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let us not go into that controversy now. You make your points, Mr. Pande.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDE: I am only formulating my questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Yes, you formulate your questions.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I want to know whether it is a fact or not that since 1960 this Nhava-Sheva port project, ia all lis various aspects, has been under the consideration of the Government and so far the examination reports have not, reached the Government and the Government is incurring more cost year after year. The Government may some day come out with a statement that because of paucity of funds this proposal may be shelved? I would like to know whether the Minister and the Government will clarify the position in this regard. I would like to know whether the statement which was made in the Lok Sabha on the 31st, July 1980 is correct or the statement given in the Rajya Sabha on the 25th July, about the Investment Board and its report, is correct. I would like to know which is correct and what the fact about, it is. What is the fact about the statement given in the Lok Sabha or the statement given in the Rajya Sabha that the Investment Board has already cleared this proposal? At what stage is this proposal now? Sir, these are the two main questions that I want the Minister to reply.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, I was the principal questioner and out of that, Sir, this half-an-hour discussion has arisen. Honourable Members have put a large number of questions and I will not repeat them, and I will not preface my question also. My simple question would be this: Is there any fishing harbour, apart from the Nhava-Sheva port? Was there any objection from the people living in that locality? Was there any objection that if the fishing harbour was established there, it would upset the ecological balance? Was any memorandum presented and, as a result of such a memorandum, has any stay order been issued and, if so, has it subsequently been vacated? I would like to know whether the so-called fishing habour is distinct and separata from the Nhava-Sheva port and the one has nothing to do with the other. These are the three basic I questions which, I hope, the honour-I able Minister would be pleased to answer.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Very good.

SHRI S. W. DHABE: Sir, I was also a party to it and I only want to ask a few questions. I would like to know whether the clearance by the Public Investment Board is possible without the Detailed Project Report being approved by the Government and, secondly, when the clearance was given by the Public Investment Board and at what cost. These are the two questions. I would like to know....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); I do not permit you. You wanted to put two questions and I have permitted you. Now, the Minister.

SHRI A. P. SHARMA: Sir, I do not know how to answer. I

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Why? If is very easy.

SHRI A. P. SHARMA: Sir, I do not know how to answer the points that have been made by my various friends. Some of them have spoken in English and some of them have spoken in Hindi. I

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: But, about the stay order, there is no problem, I think.

SHRI A. P. SHARMA-. I think I will better...

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Half of your sentences should be in English and half of them should be in Hindi.

SHRI A. P. SHARMA-. Nandaji, I that is the whole trouble. I do not believe in half-and-half.

श्री सदाशिव बागाईतकर : शर्मा जी आप हिंदी में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ।

SHRI A. P. SHARMA: I do not bslieve in half and half.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: At least you believe in your other half. *(Interruptions)*

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, that must be corrected. That is not the other half; this is 'better half. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If you go on interjecting, I will stop the whole debate.

SHRI A. P. SHARMA: Sir, the question is of delay. If you look at the whole history of establishment of Nhava Sheva Port... *(Interruptions)* I do not like to repeat the whole history from 1967 when this work started. That is why I gave them the latest position from April 1980.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: From the ecological balance... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); Please.

SHRI A. P. SHARMA: I am absolutely clear that the apprehensions of my friends are not correct. I have given the facts also about that. Still they have been trying to impute motives, they have been trying to bring in extraneous considerations. But I want to assure them about the provision of the amount in the draft. Sixth Five Year Plan. I have also told them as to how much it is going to cost now, about which Mr. Bagaitkar, my friend, has questioned—that had it been lonstructsd earlier it would have been cheaper. Yes, it would have been. But, then, li you look at the history, you will find that the delay was not only for a particular reason. You will be interested to knbw this that Nhava Sheva Port was expected to handle coal, but later on it was found that coal traffic will not materialise. This was one reason. One examination was conducted that coal should be carried, but later on it was found that this traffic will not materialise. Do you want to suggest that without justification something should be done? Then, Sir, later on, it was again examined. Sir, a port can be built only if traffic demand is there. And when the Working Group of the Planning Commission had finalised their study of this subject, a question was...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: In which year?

SHRI A. P. SHARMA: I have given you already. Mr. Mathur, again and again you want to know that. I have given you the date: April, 1980. That delay was not there for some specific reason or *the* reason advanced by any body else.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Ecological balance.

SHRI A. P. SHARMA: I have also stated in my earlier reply the reasons as to why at the stage of commissioning the detailed project report, the Minister of State for Defence Production had been there. He has listened to the people. He has submitted a report. The whole thing is under consideration of the Government, Sir.

My friend, Mr. Kulkarni, has raised a very interesting question, and that is about what my colleague said the other day in the House. Would you like me to repeat it from the proced-ing? *(Interruptions)* I quote:

"CHAIRMAN: What is the reply of the Government?" That was the question, because the Chairman also sometimes or the Vice-Chairman may

also ask *some* clarifications and I have to answer. I quote again:

'The proposal for the detailed project report has been cleared by the Public Investment Board."

Wh.'rt is the contradiction in what I have said about it and what he said earlier?

(Interruptions)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You may have rectified it.

SHRV A. P. SHARMA: The difficulty is that you are so much prejudiced. ..

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI. Not at all.

SHRI A P. SHARMA: About our action.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Why should I be prejudiced? I am interested in the project. We have heurd many people say that the Investment- Board has cleared the project. What does it mean?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If you answer these following questions, I think it will do. I am only repeating the questions asked by hon. Members. These are not my questions. Has the Public Investment Board cleared the project? That was the question of Mr. Kulkarni. Then, there have bepn certain reports in the Hindustan Times regarding ecological balance. What is your view regarding that? Then there was a question about the J committee. What is your reaction to the proposal of setting up a committee? The next question is from Mr. I Pande. If there any divergence between the reply in Lok Sabha and in Rajya Sabha? Then there is Nanda's question. Is there a fishing harbour and, if so, is it distinct from Nhava Sheva Port? You have already answered the question of Mr. Dhabe. I

SHRI A. P. SHARMA: Sir, it appears that there is a confusion about the clearance by the Public Investment Board. There are two different things, the clearance of the Detailed Project Report and the clearance of the project. The project will come at a later stage. At present, the P.I.B. has given clearance for the Detail Project Report. I have said times without number that when we were going in for commissioning of the Detailed Project Report, this objection came. Therefore, I hope that here' after there should be no confusion about the clearance of the PIB.

About the committee, I can straightaway say that there is no necessity at all. I have explained the position at this point of time. We are providing a certain amount in the Sixth Plan for the year 1980-81. I have also given the total amount that this project ig going to costus. Therefore, there is nothing to be examined by the committee and there is no necessity for a committee.

About the fishing harbour, I do not know which fishing harbour my frienci is referring to because there is only one fishing harbour of Sasun. There is a controversy about that also. Some people are protesting. We are only the contractors. The Port Trust is only the contractor. This project belongs to the food and Agriculture Ministry. So, if they want us to do the work, we will do. If they want us to stop work, we will have nothing to do.

(Interruption)

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Mr. Minister, my definite information is that the objection which has been raised by the people living in that locality was with regard to the fishing harbour and not to Nhava Sheva Port. Why have you passed stay order regarding Nhava Sheva Port? This is my question.

SHRI A. P. SHARMA: My friend is talking the same thing again and again and using words which I do not want to use. I only say that today the position is what I have stated before the House. I would like to repeat that after consideration of the Minister of State for Defence Production, further steps will be taken.

6 P.M.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: What about ecology?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You can briefly say about Mr. Pandey's point whether there is any divergence between what is said in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. And then they are insisting on ecology.

SHRI A. P. SHARMA: I am sorry, Sir, I have not been able to follow what my friend, Mr. Pandey, wanted to know. If he repeats it, I will try to reply. *(Interruptiorms)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let us leave it at that.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: What about ecology? He is afraid of replying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I cannot compel a Minister to reply to a particular point. Now, the House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 4th August, 1980 .

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 4th August, 1980.

GMGIPMRND—LS I 806 RS—22-12- 80—750.